SHRI BHUBANESWAR KALITA: This newspaper report should be enquired into, whether there is truth in it. If there is nay truth in this, this statement should be withdrawn and he should apologize because this is a very serious statement. In this statement he says that all Assamese are ULFAs, all Kalitas are ULFAs and all... (*Interruptions*) This is highly objectionable. I want the Government to enquire into this newspaper report and take suitable action. Thank you.

Demand for separate allocation of Funds for Speedy Development of Eastern U.P.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी कृपा के लिए बहुत आभारी हूं । मैं जिस विषय की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं वह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और लम्बा है लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । माननीय, आप जानते होंगे हम सब लोग और पूरा सदन देश का विकास करने और देश को महान बनाने की कल्पना कर रहा है और सरकार प्रयास भी कर रही है । लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में एक बात ले आना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले 16-17 जिले इसमें आते हैं । यह बहुत पिछड़े हुए जिले हैं ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : उत्तर बिहार नहीं है क्या ।

श्री ईश दत्त यादव : बिहार भी है माननीय ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : उसमें आ जाइये न ।

श्री ईश दत्त यादव : माननीय, यह 16-17 जिले बहुत गरीब हैं और यहां कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं । मजबूरन यहां के लोगों को कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और पंजाब में जा करके नौकरी करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है । यह प्रश्न उठा था केन्द्रीय सरकार के सामने और 1953-54 में एक पटेल आयोग की नियुक्ति हुई थी । उन्होंने संस्तुतियां भी सरकार के पास भेजी । लेकिन साधन कम रहे होंगे, संस्तुतियां लागू नहीं हुई । माननीय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं । मैं कहना चाहता हूं कि सरकार पुन: कोई एक आयोग उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के विकास के लिये बैठाये और वह आयोग जो संस्तुतियां करे उनके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, स्थायी समस्या को हल करने के लिए, वहां कल कारखाने व उद्योग लगाये जायें ताकि वहां के लोगों को जीविका मिल सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और पुन: सरकारसे निवेदन करता हूं—माननीय वित्त मंत्री जी हमारे बैठे हैं—कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अलग से धन आवंटित करें ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : वहां से तो ध्यान मंत्री ही हैं । इसलिए बहुत धन मिल सकता है । मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर होने के बाद बिहार को रोना नहीं पड़ेगा ।

श्री ईश दत्त यादव : मेरी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के त्वरित विकास के लिए तुरन्त 1200 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और उसमें भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए मैं चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी अलग से एक आयोग बनाकर कुछ अलग से विशेष धन आवंटित कर दें ताकि उन जिलों का विकास हो सके ।

श्री कपिल वर्मा (उत्तर प्रदेश) : मैं इससे अपने को एसोसिएट करता हूं । पूर्वी उत्तर प्रदेश और साथ बिहार की जो ... (व्यवधान) हालत है वह बहुत ही परेशान करने वाली है । शायद ही इतनी गरीबी मुल्क में कहीं होगी । उसकी ओर ध्यान जवाहर लाल नेहरू के जमाने में भी गया था । उसके बाद हमारी तरफ के कई प्रधान मंत्री हुए हैं लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं गया है । मैं चाहता हूं कि इस तरफ सरकार विशेष ध्यान दे और नई सरकार से मुझे उम्मीद है कि ये लोग

(श्री कपिल वर्मा)

इस पर ध्यान देंगे और इमीडिएट ही कुछ काम होना चाहिये । वहां के लोगों के आंसू पोंछने के लिए आप तुरन्त नार्थ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ करें. . . (व्यवधान) जरा डाइरेक्शन दीजिए कि कुछ रिस्पांस दें ।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): I cannot direct the Minister for executive action. I can only draw his attention. I would like to draw the attention of the Government to two developments. One, for the Eastern Uttar Pradesh, definitely a Planning Commission team was constituted under the Chairmanship of late Dr. Baljit Singh... (*Interruption*)...an economist who later became the Vice-Chancellor of Lucknow University. And some activity was started and somehow or the other it got lost somewhere. Similarly, in 1989, for North Bihar, the IDBI was asked to come and get started with the project and something was done. A seminar was organised. And there was a plan to do about North Bihar. So, everything has been lost in the political turmoil that has come. We hope that some of these specific regional development programmes will get some priority in view of the fact that the Government is trying to have regional imbalances removed.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, यह बात सही है कि उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और इधर नार्थ बिहार बहुत ही पिछड़े हैं । यहां की श्रम शक्ति इतनी रही है कि मैं समझता हूं कि कोई सूबा ऐसा नहीं बचा है जहां पर ये लोग जाकर अपनी जिंदगी बसर करने के लिए कोई छोटा-मोटा काम न कर रहे हों । विकास के सिलसिले में इतना काम करते हैं ।

एक खुशी की बात यह है कि हमारे वित्त मंत्री जी बिहार से ठहरे हैं और प्रधान मंत्री जी उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश से ठहरे हैं । अब दोनों लोगों का समन्वय भी है । इसलिए उस समन्वय के साथ काम होना चाहिये । . . . (व्यवधान) महोदय, इस बात की भी खुशी है कि पीठ पर भी बिहार ही सुशोभित कर रहा है । ऐसी स्थिति में इस प्रश्न को गम्भीरता से लेना चाहिये । और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द एक ऐसी कार्यकारी योजना की घोषणा की जाए ताकि वहां के विकास की गति को तेज किया जा सके और जिस तादाद में गरीबी है वह समस्या हल हो सके । इसलिए एक बार फिर मैं मंत्री जी से

[उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) पीठासीन हुये]

आग्रह करना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से ध्यान दिया जाये । इससे जो आने वाली पीढ़ी है वह हमेशा आप लोगों को याद करेगी क्योंकि उनके लिए लिए और देश के लिए आप लोग कुछ करने जा रहे हैं ।

श्री रफीक आलम (बिहार) : अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा ।

श्री राम नरेश यादव : कभी नहीं होने वाला है यह भी बात सही है । इस से बढ़िया मौका नहीं मिलने वाला है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि खड़े होकर सदन को आश्वस्त भी करें कि क्या कदम उठाने जा रहे हैं ।

SHRI KAPIL VERMA: (Uttar Pradesh): The whole House associates with it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): And I also belong to Bihar.

श्री राम नरेश यादव : अच्छा, फिर आप भी बिहार के ठहरे । इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी, जरा खड़े होकर बता दीजिए कि क्या योजना आप देने जा रहे हैं; ताकि लोगों की विकास गति तो सही हो सके । यह मानवता के नाम पर होगा ।

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: (Bihar): I would particularly like to emphasise that the Ministry of Finance and the institutions associated with the Ministry of Finance are the greatest culprits so far as under-development of Bihar is concerned.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Your own Minister is sitting here.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: I am emphasising because both the Finance Secretary as well as the Finance Minister are sitting here.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : इससे एसोसिएट करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस सवाल को मैं इस सदन में पिछले तीन साल से उठता रहा कि फ्रेट पालिसी जब तक नहीं बदली जाएगी, तब तक बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का कायाकल्प नहीं होगा, वहां के लोगों के तन पर वस्त्र नहीं जुड़ेगा । हमें उचित रायल्टी नहीं मिलती है । जहां खनिज संपदा और तेल की रायल्टी असम को 37 प्रतिशत, गुजरात को 37 प्रतिशत मिलती है, हमको लोहे, आयरन ओर पर डेढ़ प्रतिशत मिलता है, कोयले पर 2 प्रतिशत मिलती है । तो मैं ठोस बात बता रहा हूं, जिस पर इनको ध्यान देना जरूरी है ।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): I would like to respond briefly to the sentiments which have been expressed by various Members on the subject. On my part, I would like to reiterate the deep commitment of the Government to the development of all the backward areas in the backward States. I think this is a commitment which finds a mention in our Constitution. This is a commitment which has been a part of our national heritage and we are very determined to see that the regional imbalances are removed and whatever steps are necessary to remove these imbalances, the present Government is committed to take them up.

Alleged mismanagement in the Paradip Phosphates Limited

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Sir, it is a very serious matter which has been repeatedly brought to the notice of the Central Government since 1986 regarding mismanagement in Paradip Phosphates Ltd. This is a joint venture having 51 per cent equity share of the Government of India and 49 per cent share of the Republic of Nauru. Very recently, it has been reported in the press, that the President of Nauru during his last visit, expressed his intention to take back the money they have invested in this project. Very often, it is an excuse advanced by a public sector undertaking, and likewise, labour problem is another excuse advanced as the cause of loss in the project. But the reality is that mismanagement, corrupt practices and 5-Star hotel culture by top executives coupled with failure to honour the rules and the law of the land by the top officials, are the reasons besides an attempt for an artificial closure by these officers in order to get away with the collected money finding the Central Government's shaky involvement to go into their shady deals, as a reward.

The workers were shocked to identify the corrupt practices of the officials and have submitted a memorandum to the President and to the Prime Minister of the country in 1986. The people's representative from Orissa raised this issue in this august House on 26-11-1986, 15-5-1990, and on 20th January 1990 three Lok Sabha Members wrote to the Deputy Prime Minister and requested for immediate intervention. Again on 17-5-1990, our colleague, the President of the labour union brought this matter to the notice of the Deputy Prime Minister, and again on 24-5-90, we ten Members of Parliament belonging to Lok Sabha and Rajya Sabha presented a memorandum to Deputy Prime Minister who assured immediate action in the matter. But nothing happened except dismissal of regular